

दिनांक 4 सितम्बर, 1984

सं. भो. वि./सोनीपत/88-84/33333—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० महेश बूड प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, जेवड़ा, बहालगढ़ (सोनीपत) के श्रमिक श्री प्रहलाद सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए. एस. ओ. ई.-अम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री प्रहलाद सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. भो. वि./सोनीपत/88-84/33840—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० महेश बूड प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, जेवड़ा, बहालगढ़ (सोनीपत), के श्रमिक श्री किशोरी लाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए. एस. ओ. ई.-अम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री किशोरी लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. भो. वि./सोनीपत/88-84/33847—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० महेश बूड प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, जेवड़ा बहालगढ़ (सोनीपत), के श्रमिक श्री कंचन प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए. एस. ओ. ई.-अम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है, या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री कंचन प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. भो. वि./सोनीपत/88-84/33854—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० महेश बूड प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, जेवड़ा बहालगढ़ (सोनीपत), के श्रमिक श्री राम किशन तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इस को द्वारा मरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-अम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864-ए.ए.ओ. (ई.)-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहताक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :-

क्या श्री राम विर्गन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

एम. के. महेश्वरी,

संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,

अम धिभाग I

दिनांक 3 सितम्बर, 1984

स.ओ.वि./सोनीपत/19-84/35508-—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं आरगनो रयडू प्रालि, इण्डस्ट्रियल एरिया, सोनीपत, के श्रमिक श्री शिव नाथ तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं :

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इस को द्वारा मरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-अम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864-ए.ए.ओ. (ई.)-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहताक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :-

क्या श्री शिव नाथ की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

स.ओ.वि./सोनीपत/194-84/35516-—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं मेटाकेम इण्डस्ट्रीज खेवड़ा, रोड, बहालगढ़, सोनीपत, के श्रमिक श्री गोपाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इस को द्वारा मरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-अम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864-ए.ए.ओ. (ई.)-70/1348 दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहताक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :-

क्या श्री गोपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

स.ओ.वि./सोनीपत/194-84/33522-—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं मेटाकेम इण्डस्ट्रीज, खेवड़ा रोड, बहालगढ़, सोनीपत, के श्रमिक श्री राकेश कुमार शर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई

गणियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए. एस. प्रो. (ई) 70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राकेश कुमार शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

मं. आ वि./मोनोपत/194-84/33529.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. मेटाकेम इण्डस्ट्रीज, सेवड़ा रोड, जयपुरम, मोनोपत, के श्रमिक श्री भूरा मल वर्मा तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद

प्रारंभिक हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, श्रव. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए. एस. प्रो. (ई) 70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री भूरा मल वर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

मं. आ वि./मोनोपत/196-84/33536.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. अशोका थियेटर प्रा. लि., रोहतक, के श्रमिक श्री शान्ति स्वरूप तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है :

प्रारंभिक हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, श्रव. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए. एस. प्रो. (ई) 70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री शान्ति स्वरूप की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

दिनांक 1 सितम्बर, 1984

मं. आ वि./मोनोपत/195-83/33903.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एम्के इण्टरनेशनल एम-4, जेण्डरुवाल एरिया, मोनोपत, के श्रमिक श्री मंजालिया तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

प्रारंभिक हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, श्रव. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए. एस. प्रो. (ई) 70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री मंजालिया की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?